प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

सचिवालय सुधार

1. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना
2. ई-ऑफिस
3. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को कम करना

मासिक रिपोर्ट | मार्च 2026

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषय सूची

1. मुख्य-मुख्य बातें, मार्च 2026..1

I. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वय..1

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियाँ (मार्च 2026)..2

III. लंबित मामलों में कमी..2

2. औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग)..3

2.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (मार्च 2026)..3

2.2. डिलेयरिंग की स्थिति (मार्च 2026)..4

3. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन..6

3.1 ई-ऑफिस एनालिटिक्स..6

3.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी..7

3.3. ई-फाइल सृजन (मार्च 2026)..8

3.4. अंतर विभागीय फ़ाइल संचलन..8

3.5. ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर)..9

3.6. ई-ऑफिस एनालिटिक्स..10

4. विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना..14

4.1. कुल अर्जित राजस्व..14

4.2 स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (मार्च 2026)..15

4.3. खाली हुआ स्थान (मार्च 2026)..15

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों में खाली हुआ स्थान..16

4.4. स्वच्छता अभियान स्थल (मार्च 2026) ...17

4.5. छँटाई/बंद की गई फिजिकल फाइलें (मार्च 2026)...17

5. पहले- बाद में ...18

6. सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ - पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां ...20

7. मंत्रालयों/विभागों का मापदंड-वार कार्य निष्पादन ...21

8. इन फोकस: खान मंत्रालय ...23

8.1. कार्यालय का कुशल प्रबंधन ...23

8.2. स्क्रैप निपटान ...23

8.3 खान मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ ...24

8.4 निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना...27

8.5 मार्च 2026 में उल्लेखनीय उपलब्धियां ...27

09. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन ...28

10. सरकार में लंबित मामलों को कम करने पर कार्यालय ज्ञापन...29

11. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन ...30

अनुलग्नक I : अपलोड नहीं किए गए आँकड़े 32

अनुलग्नक II: संक्षेपाक्षरों की सूची ...33

1 मुख्य-मुख्य बातें
मार्च 2026

I. ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

59

मंत्रालयों/विभागों के पास ई-फाइलों का कम से कम 90 प्रतिशत हिस्सा है

15

मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-रिसीट्स हैं

16

मंत्रालयों/विभागों का औसत ट्रांजैक्शन स्तर 4 या 4 से कम है

ई-फाइलों का उपयोग (%)
90.29%

मार्च 2026: 5,58,102 रिसीट्स में से, 5,33,169 ई-रिसीट्स थीं

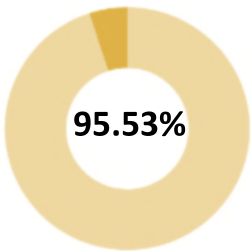

औसत ट्रांजैक्शन स्तर

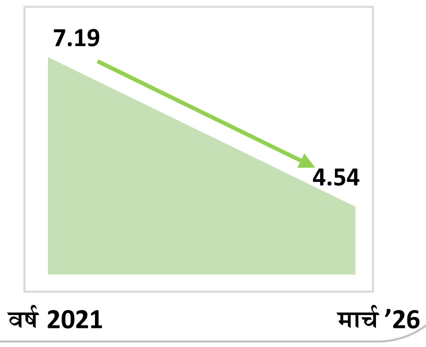

सक्रिय,बंद की गई और कुल ई-फ़ाइलों के मासिक आँकड़े

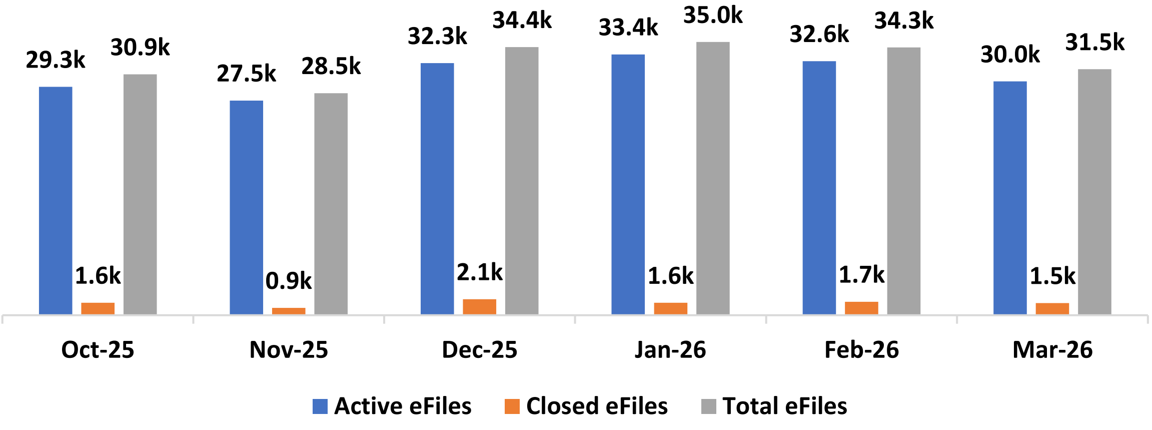

1 मुख्य-मुख्य बातें मार्च 2026

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां (मार्च 2026)

12,149
स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

13,76,378
वर्ग फुट स्थान खाली हुआ

139,31,29,179
कचरा निपटान से अर्जित राजस्व

III. लंबित मामलों में कमी

निपटान

- ✓ 5,81,684 लोक शिकायतें
- ✓ 28,668 लोक शिकायत अपीलें
  1,060 संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र
- ✓ 401 राज्य सरकारों से प्राप्त पत्र
- ✓ 197 आईएमसी संदर्भ
- ✓ 461 पीएमओ से प्राप्त पत्र

पूरे किए गए संसदीय आश्वासन

95

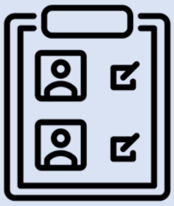

रिकॉर्ड प्रबंधन

- ✓ 2,34,610 000 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई और 1,22,226 फाइलों की छंटाई की गई ।

2 औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग)

मुख्य व्याख्या

केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 2021 के 7.19 से घटकर मार्च, 2026 में केवल 4.54 रह गया है, जिससे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होगी और दक्षता बढ़ेगी।

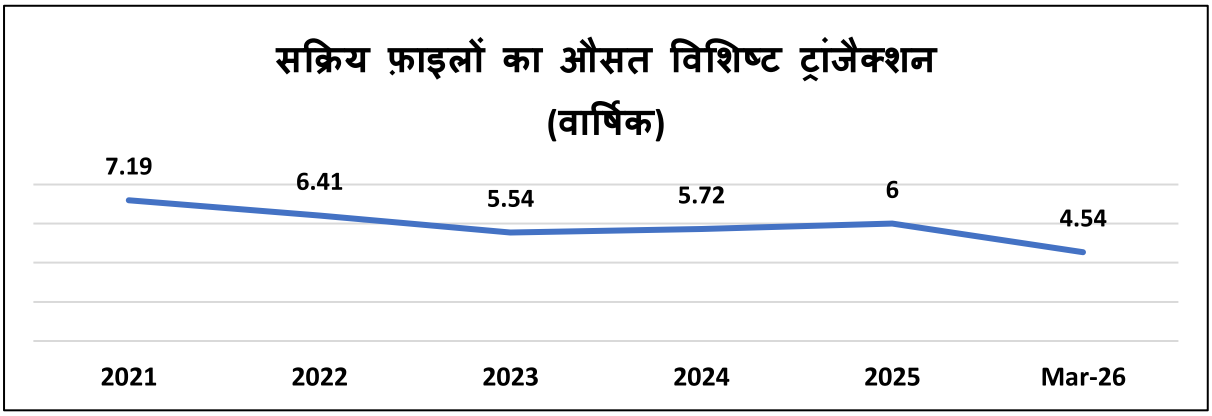

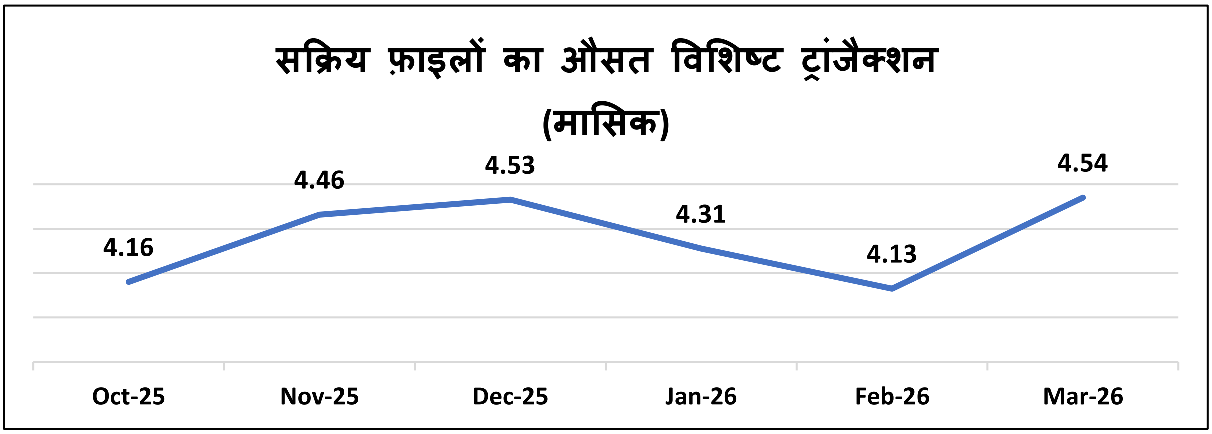

2.1 डिलेयरिंग प्रवत्ति (मार्च 2026)

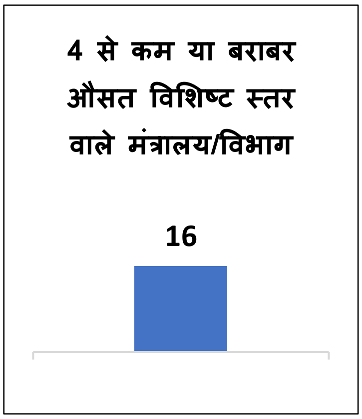

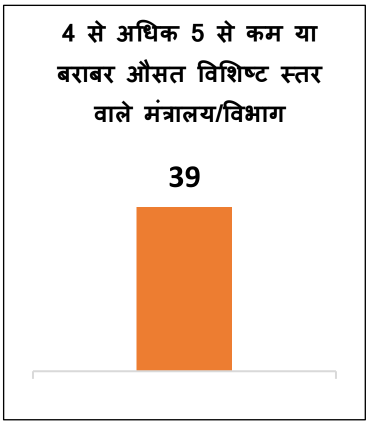

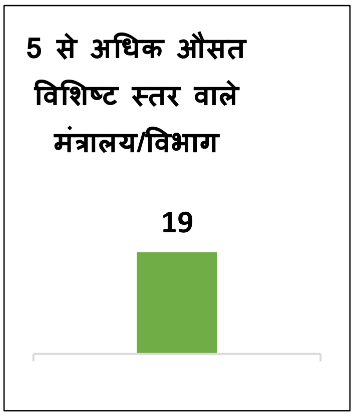

2.2. डिलेयरिंग की स्थिति

निम्नलिखित ग्राफ, मार्च, 2026 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तरों को दर्शाता है:

क ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर ≤ 4 तक है

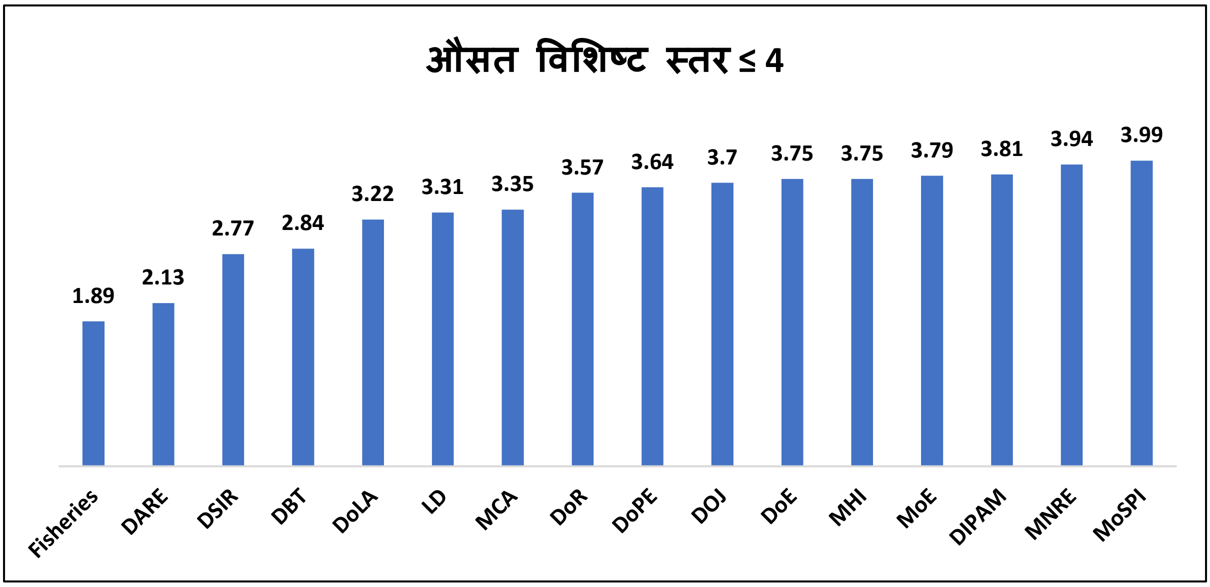

ख. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक और 5 से कम या बराबर है

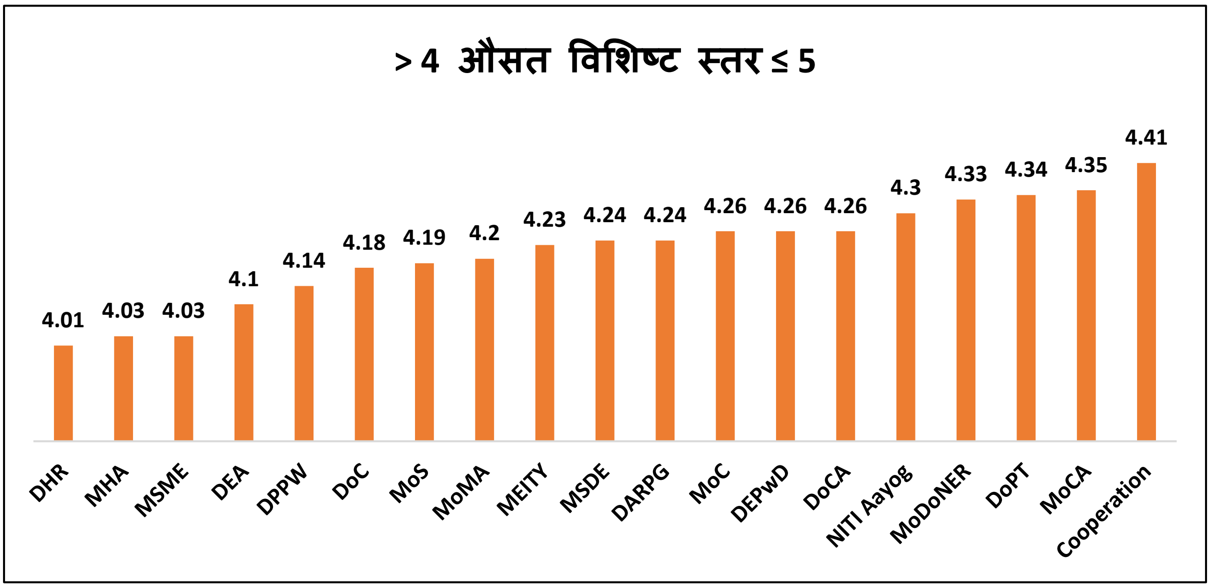

ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक और 5 से कम या बराबर है (जारी...)

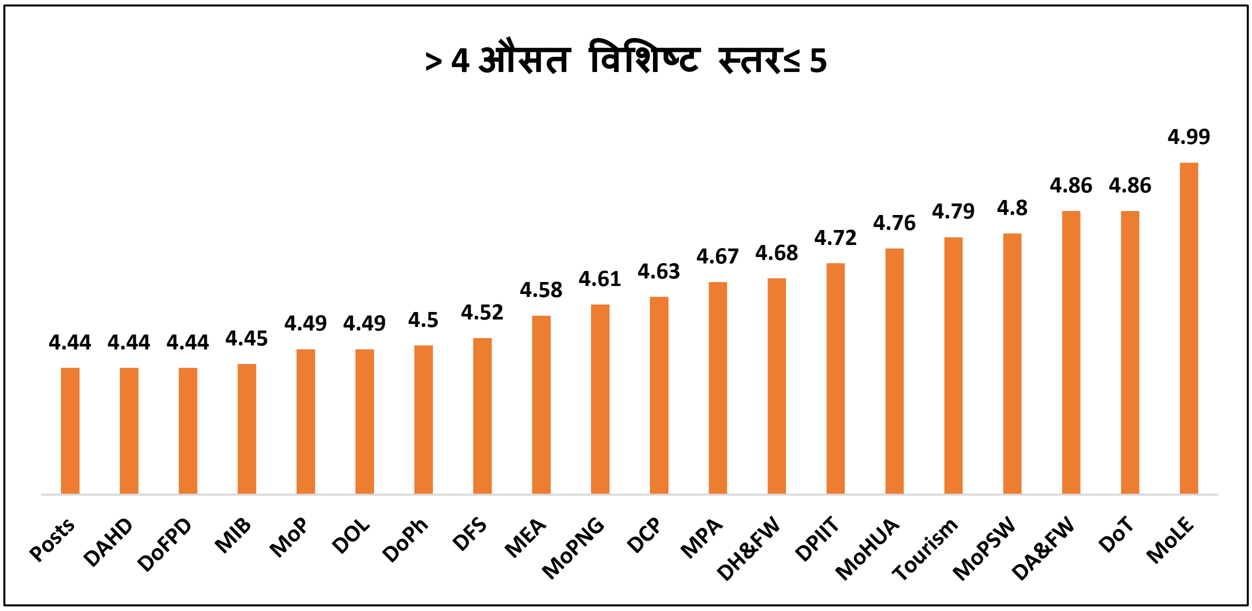

ग. 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग

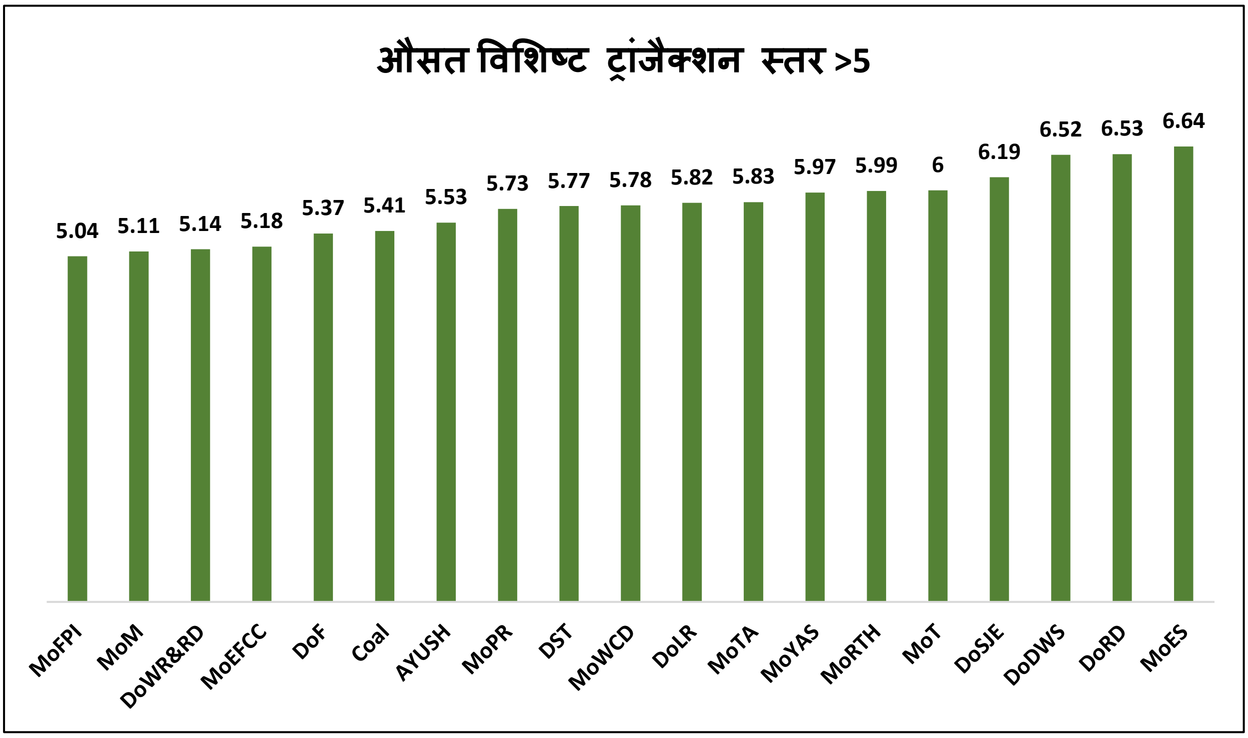

3 ई-ऑफिस एनालिटिक्स और कार्यान्वयन

अवलोकन

ई-ऑफिस का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के लिए एक पेपरलेस, कुशल और पारदर्शी डिजिटल कार्यस्थल बनाना है, जिससे एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना आसानी से प्राप्त हो सके और उसे आसानी से साझा किया जा सके।

केंद्रीय सचिवालय में वर्ष 2014 से ई-ऑफिस को अपनाने में काफी तेजी आई है। मंत्रालयों/विभागों ने ई-ऑफिस के संस्करण 5.6 से अधिक उन्नत संस्करण 7.x को अपनाया है, जो प्रयोकतानुकूल, अनुकूलित, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और मोबाइल और टैबलेट उपकरणों के साथ अच्छे से कार्य करता है।

केंद्रीय सचिवालय के लिए उन्नत निर्णय सपोर्ट और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रशासनिक/वित्तीय कंट्रोलेबल केपीआई शामिल हैं।

ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड इंटरफ़ेस: यूआरएल: https://vishleshan.eoffice.gov.in/ डैशबोर्ड केवल एनआईसी नेट पर उपलब्ध है। वर्तमान में यह भारत सरकार के सभी सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (जिनके संबंध में केवल एनआईसी ईमेल और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ एनआईसी से विशिष्ट अनुरोध किया जाना है) के लिए सुलभ है।

ई-ऑफिस: स्केल और कार्यान्वयन परिदृश्य

- ✓ केंद्रीय सचिवालय के 74 मंत्रालय/विभाग ई ऑफिस में कार्य कर रहे हैं ।
- ✓ इसे देशभर में 1400 से अधिक संगठनों द्वारा अपनाया गया है, जिनमें मंत्रालय, राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय और अन्य संस्थान शामिल हैं, जिनके 17 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

विशलेशन डैशबोर्ड प्रमुख परिचालन आयामों का एकीकृत दृश्य प्रदान करता है:

ई फाइल्स और पी फाइल्स के आँकड़े	ई फ़ाइल मूवमेंट की स्थिति (डिस्टिंक्ट लेवल)	अंतर-मंत्रालयी/विभागीय फ़ाइल मूवमेंट
पार्ट फ़ाइलों के आँकड़े	रिसीट की स्थिति	वीपीएन यूसेज
साइनिंग यूसेज	फ़ाइलों पर की गई कार्रवाई के आँकड़े	फ़ाइलों की पेंडेंसी के आँकड़े

3.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी

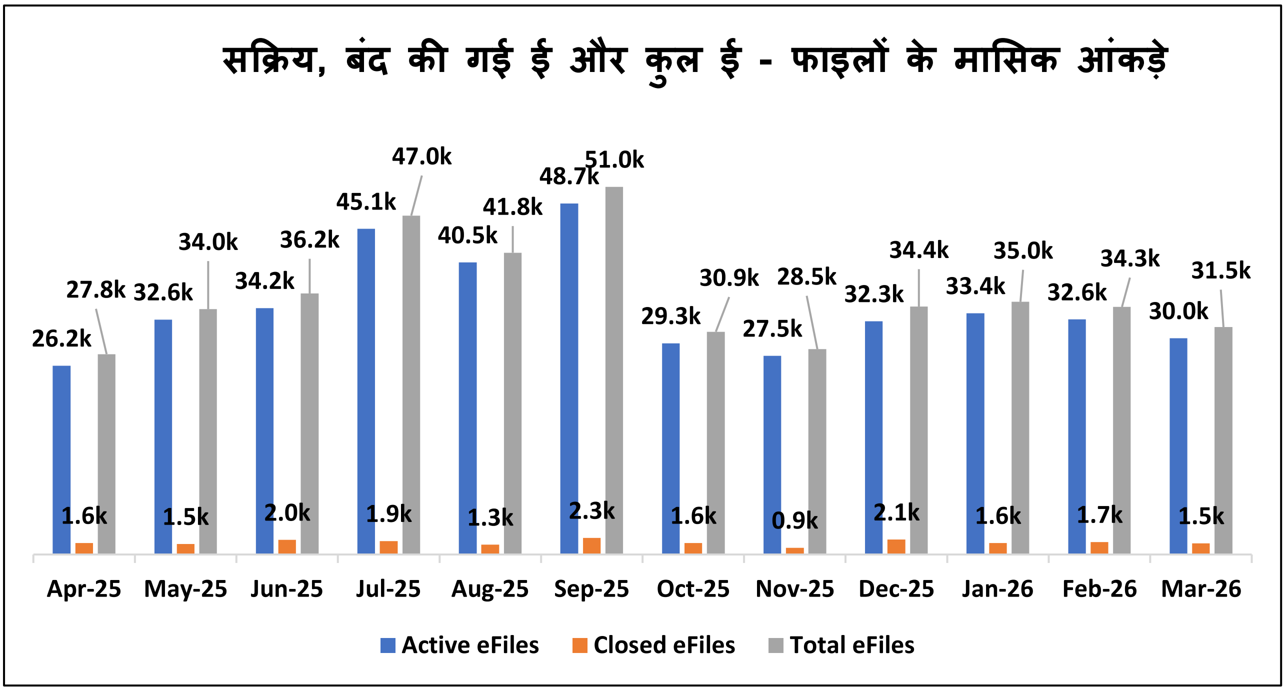

कुल ई-फाइलें अप्रैल, 2025 में **27.8 हजार** से मार्च, 2026 में **31.5 हजार** तक पहुंच गई हैं। यह मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निरंतर अपनाए जाने और सक्रिय उपयोग को दर्शाता है, जिसमें सक्रिय और बंद की गई फाइलों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है - जो ***बेहतर डिजिटल वर्कफ़्लो और फ़ाइल प्रबंधन को दर्शाता है।***

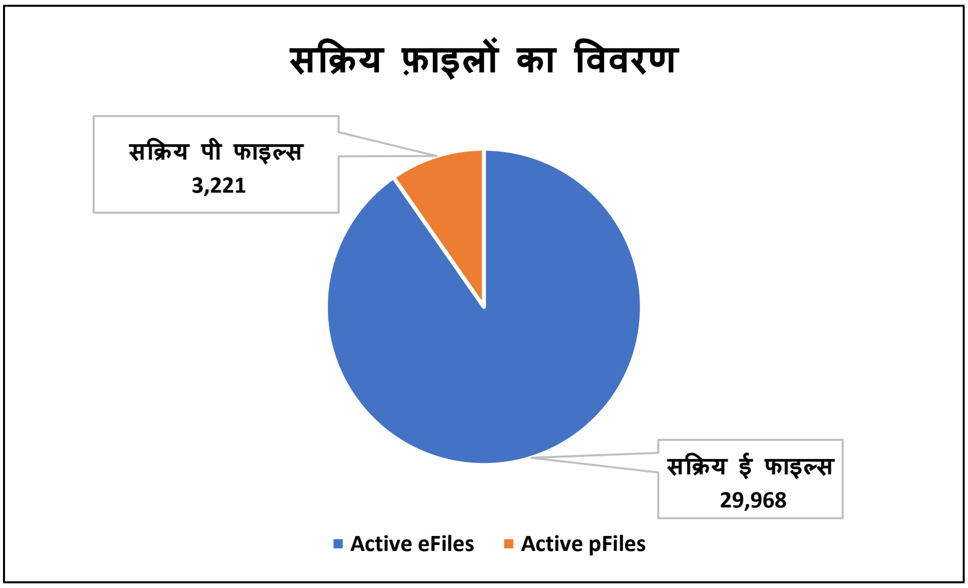

मार्च, 2026 में कुल **सक्रिय फाइलों** में ई-फाइलों का हिस्सा **90.29%** था, जो फिजिकल फाइलों की तुलना में डिजिटल फाइलों के अधिक उपयोग को दर्शाता है।

3.3. ई-फ़ाइलों का सृजन

मार्च, 2026 माह में सक्रिय ई-फाइलों में <90 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले मंत्रालय/विभाग:

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग का नाम	ई-फ़ाइलों का %शेयर
1	नागर विमानन मंत्रालय	89.86%
2	भारी उद्योग मंत्रालय	88.05%
3	संस्कृति मंत्रालय	85.63%
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	84.76%
5	उपभोक्ता कार्य विभाग	84.24%
6	परिवार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	81.72%
7	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	80.67%
8	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	79.96%
9	शिक्षा मंत्रालय	78.62%
10	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	75.46%
11	दूरसंचार विभाग	74.30%
12	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	66.11%
13	गृह मंत्रालय	65.36%
14	आयुष मंत्रालय	62.61%
15	राजभाषा विभाग	56.90%

3.4. अंतर-मंत्रालयी/विभागीय फाइल संचलन

- अंतर-मंत्रालयी फाइल संचलन में शीर्ष मंत्रालय/विभाग – मार्च, 2026

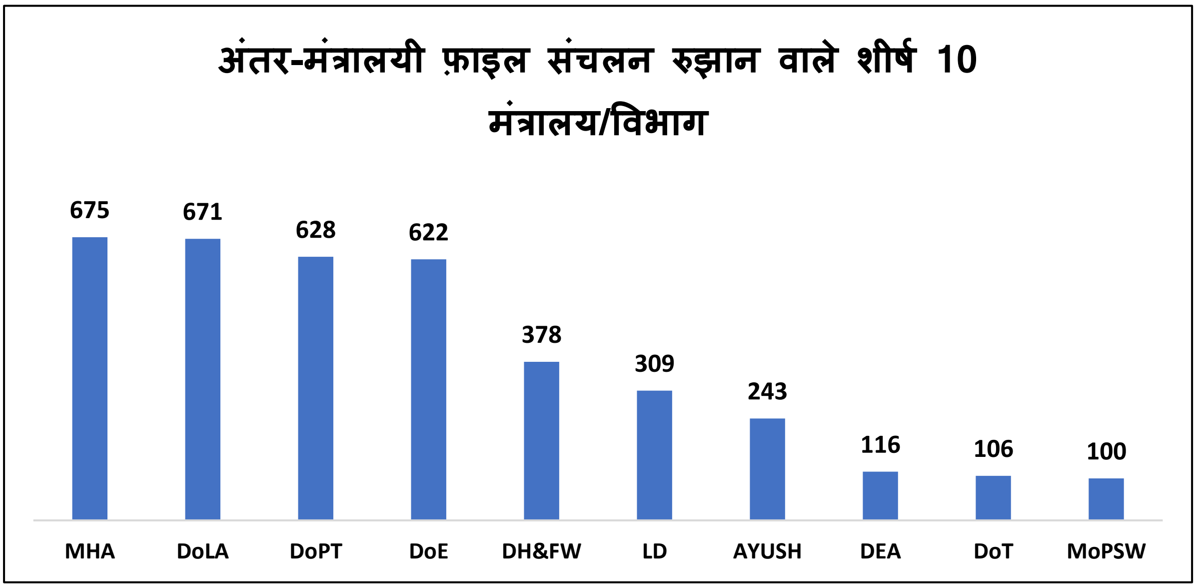

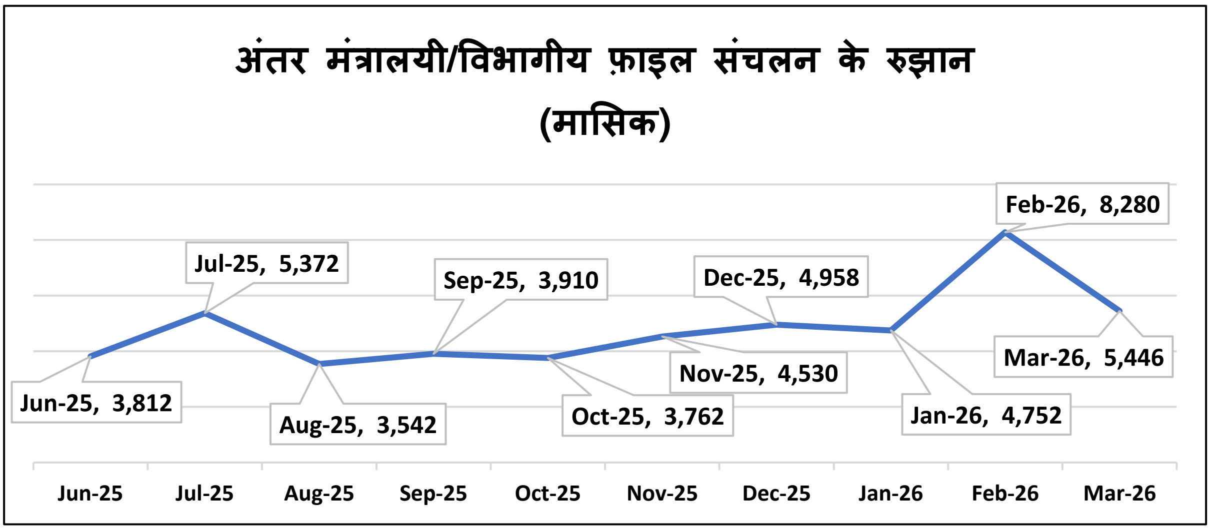

3.5. ई-रिसीट्स अपनाना (ई-रिसीट्स का % हिस्सा)

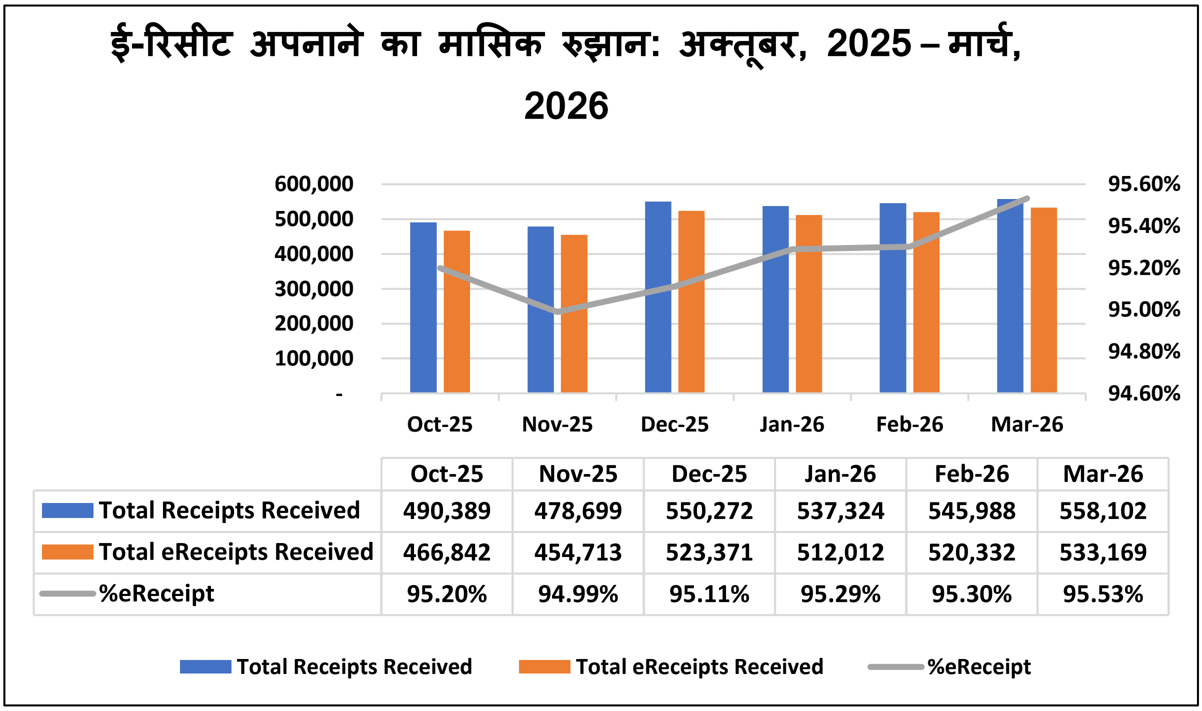

	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26
Total Receipts Received	490,389	478,699	550,272	537,324	545,988	558,102
Total eReceipts Received	466,842	454,713	523,371	512,012	520,332	533,169
%eReceipt	95.20%	94.99%	95.11%	95.29%	95.30%	95.53%

पिछले छह महीनों में ई-रिसीट्स का शेयर लगातार 94% से ऊपर बना हुआ है, जो **मार्च, 2026 में 95.53%** के उच्चतम स्तर पर है - यह मंत्रालयों/विभागों में रिसीट प्रबंधन में निरंतर डिजिटल अडॉपशन का संकेत

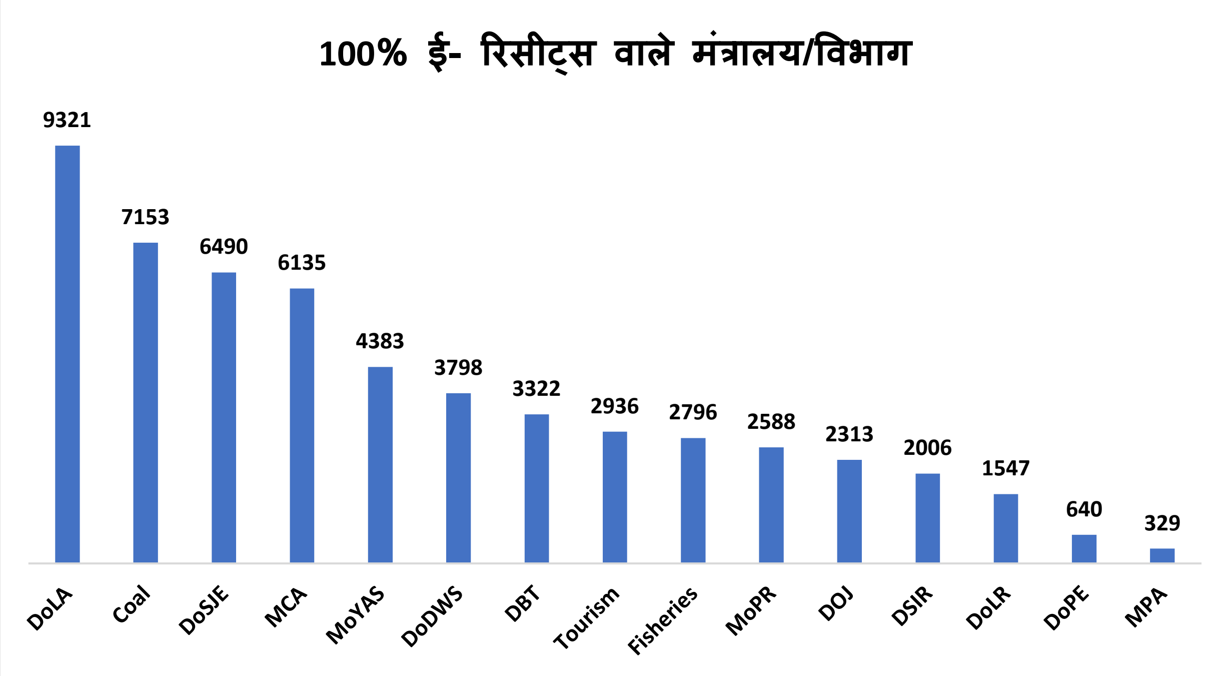

3.6. ई-ऑफिस विश्लेषण

मार्च, 2026 के लिए मंत्रालय-वार विश्लेषण संक्षेप में इस प्रकार है:

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
1	गृह मंत्रालय	65.36%	79.37%	34.60%
2	विधि कार्य विभाग	100.00%	100.00%	12.29%
3	शिक्षा मंत्रालय	78.62%	95.71%	40.78%
4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	81.72%	93.94%	51.40%
5	आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय	95.89%	99.25%	54.78%
6	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	99.73%	99.93%	33.58%
7	वाणिज्य विभाग	99.70%	98.34%	34.35%
8	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	79.96%	99.98%	47.73%
9	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	75.46%	99.68%	52.71%
10	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.96%	63.10%

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
11	डाक विभाग	99.61%	99.69%	40.74%
12	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	99.85%	99.32%	56.87%
13	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	97.60%	92.25%	41.86%
14	दूरसंचार विभाग	74.30%	89.55%	53.90%
15	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	90.57%	97.30%	36.29%
16	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	80.67%	90.40%	37.79%
17	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संवर्धन विभाग	100.00%	99.97%	57.34%
18	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100.00%	99.98%	67.33%
19	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	92.72%	73.89%	23.74%
20	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय	93.66%	94.38%	51.11%
21	ग्रामीण विकास विभाग	100.00%	99.98%	72.25%
22	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	100.00%	93.92%	43.51%
23	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	66.11%	85.85%	59.70%
24	आयुष मंत्रालय	62.61%	78.57%	72.44%
25	नीति आयोग	100.00%	98.52%	43.28%
26	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	99.74%	100.00%	75.48%
27	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	93.07%	85.32%	26.93%
28	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	98.94%	97.35%	39.36%
29	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	100.00%	100.00%	78.98%
30	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	100.00%	100.00%	80.13%
31	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	100.00%	99.92%	40.73%
32	विदेश मंत्रालय	100.00%	99.92%	48.03%

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
33	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	31.80%
34	कोयला मंत्रालय	100.00%	100.00%	61.63%
35	विद्युत मंत्रालय	100.00%	99.98%	45.49%
36	संस्कृति मंत्रालय	85.63%	95.56%	45.67%
37	सहकारिता मंत्रालय	91.48%	94.73%	43.97%
38	डीएचआर विभाग - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	94.55%	89.56%	25.88%
39	नागर विमानन मंत्रालय	89.86%	99.77%	50.70%
40	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	100.00%	99.98%	42.03%
41	खान मंत्रालय	99.25%	99.93%	58.06%
42	वस्त्र मंत्रालय	99.55%	83.58%	69.59%
43	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	99.58%	99.95%	37.64%
44	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	90.04%	99.22%	48.90%
45	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	99.37%	99.93%	66.67%
46	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00%	99.46%	75.58%
47	उपभोक्ता कार्य विभाग	84.24%	99.92%	37.04%
48	इस्पात मंत्रालय	98.85%	97.63%	32.32%
49	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	100.00%	97.08%	66.48%
50	पंचायती राज मंत्रालय	100.00%	100.00%	68.92%
51	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	99.47%	99.77%	43.36%
52	विधायी विभाग	100.00%	99.80%	27.54%
53	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा	84.76%	99.98%	40.44%
54	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	97.88%	91.54%	37.04%

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	ई-रिसीट का %	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
55	भारी उद्योग मंत्रालय	88.05%	99.74%	35.38%
56	उर्वरक विभाग	98.58%	99.75%	61.79%
57	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	98.91%	99.69%	47.50%
58	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	100.00%	100.00%	12.39%
59	पर्यटन मंत्रालय	99.55%	100.00%	53.64%
60	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	96.95%	90.26%	45.36%
61	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.00%	99.81%	78.72%
62	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	100.00%	100.00%	6.85%
63	औषध विभाग	100.00%	99.51%	50%
64	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	100.00%	99.89%	36.51%
65	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	100.00%	98.46%	37.29%
66	राजभाषा विभाग	56.90%	69.37%	43.14%
67	न्याय विभाग	100.00%	100.00%	10.87%
68	भूमि संसाधन विभाग	100.00%	100.00%	73.33%
69	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	94.44%	95.51%	45.71%
70	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	100.00%	99.88%	3.33%
71	सार्वजनिक उद्यम विभाग	100.00%	100.00%	23.08%
72	मत्स्य पालन विभाग	93.96%	100.00%	0%
73	दीपम - वित्त मंत्रालय	100.00%	99.89%	31.25%
74	संसदीय कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	66.67%

जिन मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है, उनके द्वारा डिलेयरिंग/डेलिगेशन की समीक्षा की जानी है।

4 विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना

कुल उपलब्धियां (2021 – मार्च, 2026)

मापदंड	एससी1.0 - एससी4.0	दिसंबर'24-अगस्त'25	एससी 5.0	दिसंबर'25 -मार्च '26	कुल
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)	2,364.05	1,007.1	833.92	432.14	**4,637.21**
खाली हुआ स्थान (लाख वर्ग फुट में)	643.82	57.23	233.75	54.75	**989.55**
स्वच्छता अभियान स्थल	11,49,935	60,442	11,59,783	23,408	**23,93,568**
फाइलों की छंटाई (लाख में)	131.4	6.81	29.52	5.99	**173.72**

आँकड़े विशेष अभियानों **(एस.सी. 1.0 - एस.सी. 5.0)** और सचिवालय सुधारों की निरंतर गति को दर्शाते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, कुल उपलब्धियों में शामिल हैं: स्क्रैप निपटान से **₹4,637.21 करोड़** की आय हुई, **989.55 लाख वर्ग फुट** कार्यालय स्थान खाली हुआ, **23.94 लाख स्थलों को** स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत लाया गया और **173.72 लाख फाइलों का निपटान किया गया।** यह निरंतर प्रगति, स्वच्छता के संस्थागतकरण और दैनिक शासन में दक्षता-उन्मुख परिपाटियों की पुष्टि करती है।

4.1. कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)

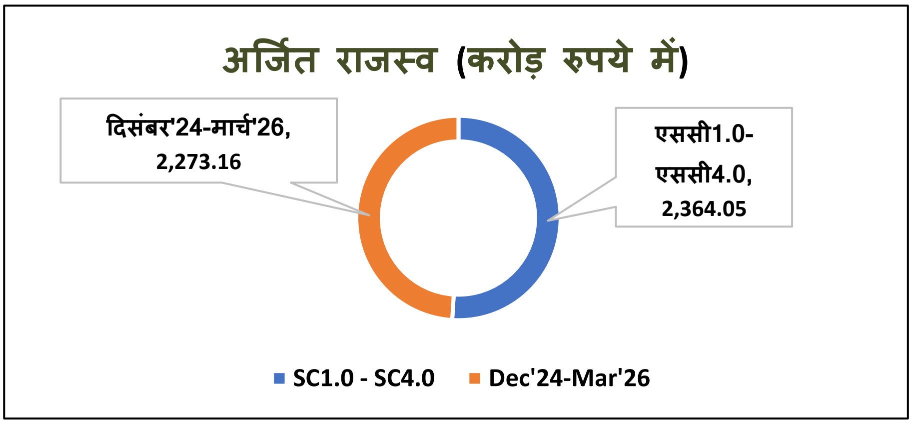

कचरा निपटान के माध्यम से अर्जित कुल **₹4,637.21 करोड़** राजस्व में से, **₹2,364.05 करोड़** का राजस्व, **विशेष अभियान 1.0 और विशेष अभियान 4.0** के दौरान प्राप्त हुआ। यह गति **दिसंबर, 2024 से अगस्त, 2025** में **1007.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व के साथ जारी रही, इसके बाद ₹833.92** करोड़ का राजस्व, **विशेष अभियान 5.0** के दौरान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, कचरा निपटान से **दिसंबर, 2025 और मार्च, 2026 के दौरान**, **432.14** करोड़ रु. राजस्व के रूप में प्राप्त हुए जो विशेष अभियानों के सभी चरणों में निरंतर राजस्व सृजन को दर्शाता है।

4.2. कचरा निपटान से अर्जित राजस्व (मार्च 2026)

कुल अर्जित राजस्व (कचरा निपटान से) 139.31 करोड़ रुपये
शीर्ष 5 मंत्रालयों/विभागों द्वारा अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)

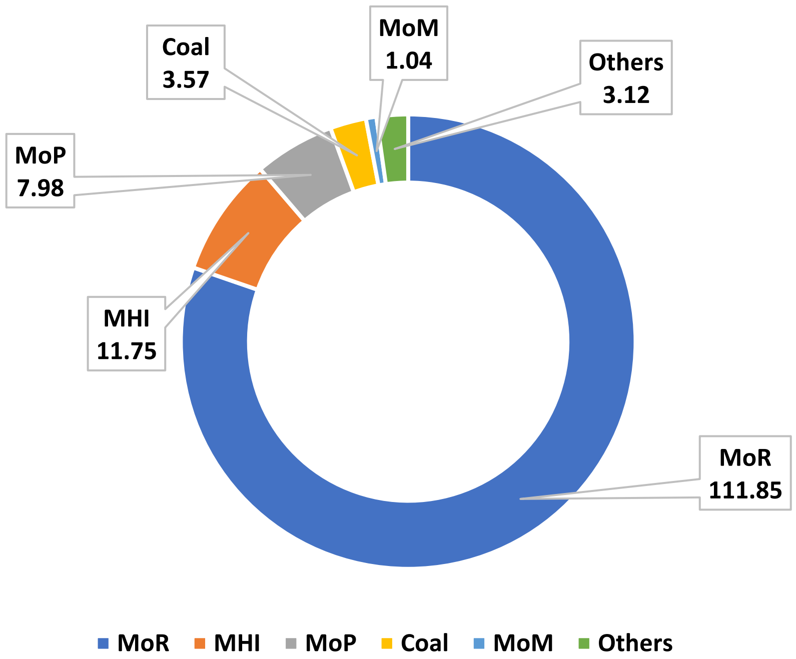

4.3. खाली हुआ स्थान (मार्च, 2026)

शीर्ष 5 मंत्रालयों/विभागों द्वारा खाली किया गया कुल स्थान (वर्ग फुट में) 16,34,141 वर्ग फुट

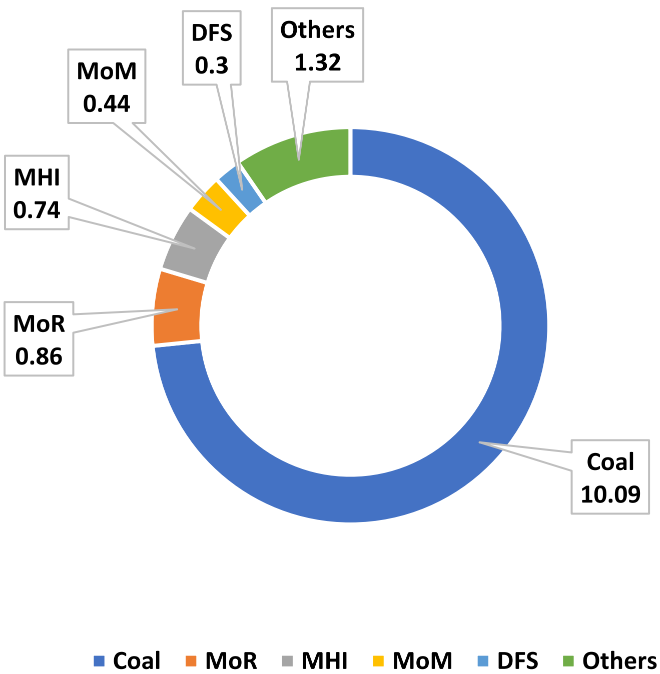

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा खाली हुआ स्थान

- **कोयला मंत्रालय:** मार्च, 2026 में कुल 10,09,699 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, खाली हुए स्थान के आधार पर शीर्ष 3 ज़ोन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	साइट/संगठन	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	8,46,830.9
2.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	72,841
3.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	27,500

- **रेल मंत्रालय:** मार्च, 2026 में कुल 85,540 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, खाली हुए स्थान के आधार पर शीर्ष 3 ज़ोन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	साइट/संगठन	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	उत्तर-पश्चिम रेल	39,773
2.	मध्य रेल	17,928
3.	एमसीएफ रायबरेली	9,500

- **भारी उद्योग मंत्रालय:** मार्च, 2026 में कुल 74,138 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, खाली हुए स्थान के आधार पर शीर्ष 3 ज़ोन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	ज़ोन	खाली हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	20,850
2.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स	15,800
3.	ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर	15,000

4.4. स्वच्छता अभियान स्थल (मार्च, 2026)

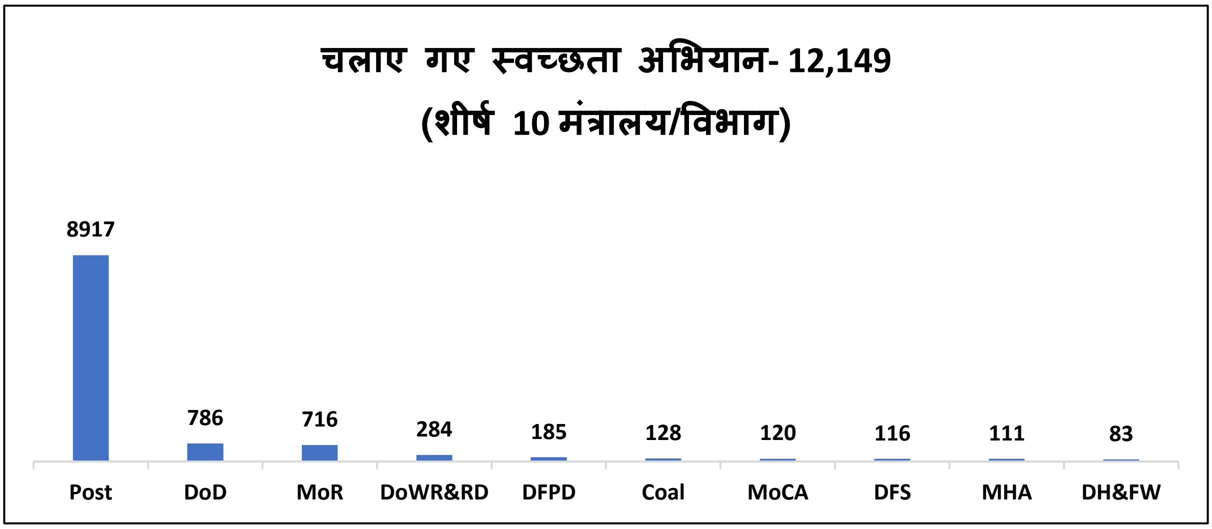

चलाए गए कुल 12,149 स्वच्छता अभियानों में से, **डाक विभाग ने कुल अभियानों का लगभग 73.4 प्रतिशत** अभियान चलाया, इसके बाद रक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संवर्धन विभाग इत्यादि का स्थान है जो इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वच्छता पहलों में मजबूत और निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

4.5. छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (मार्च, 2026)

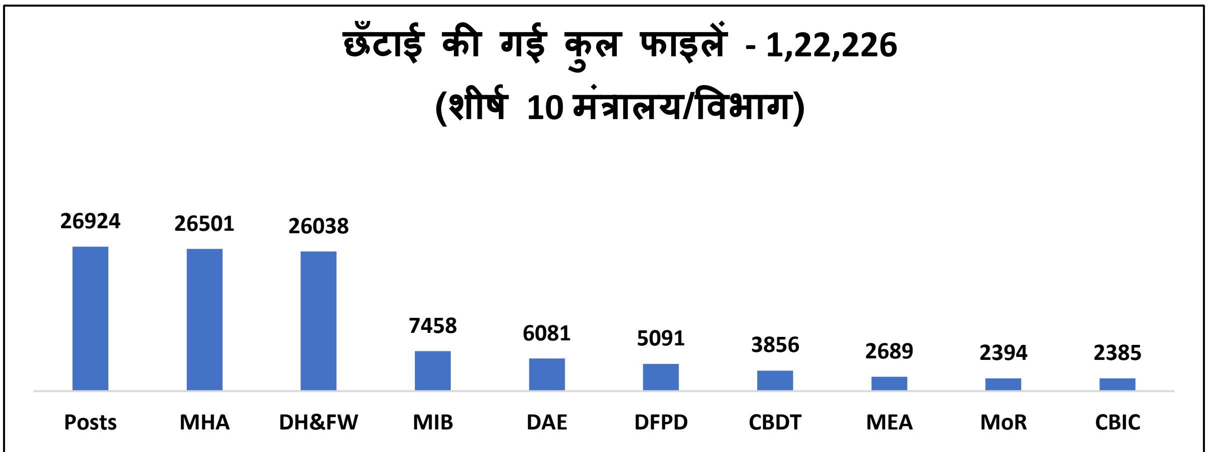

छंटाई की गई 1,22,226 फाइलों में से,**डाक विभाग ने 26,924** फाइलों की छँटाई करके पहला स्थान प्राप्त किया इसके बाद **गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** में क्रमशः **26,501 और 26,038 फ़ाइलों की छँटाई की गई**। यह दर्शाता है कि प्रमुख मंत्रालय, अव्यवस्था को दूर करने और फाइल प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं।

5 पहले- बाद में

मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए सचित्र साक्ष्य-मार्च- 2026

पहले

बाद में

पुराने फर्नीचर और मेटल स्क्रैप का निपटान , प्र.सीसीआईटी,दिल्ली तहत केंद्रीय राजस्व भवन, **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)**

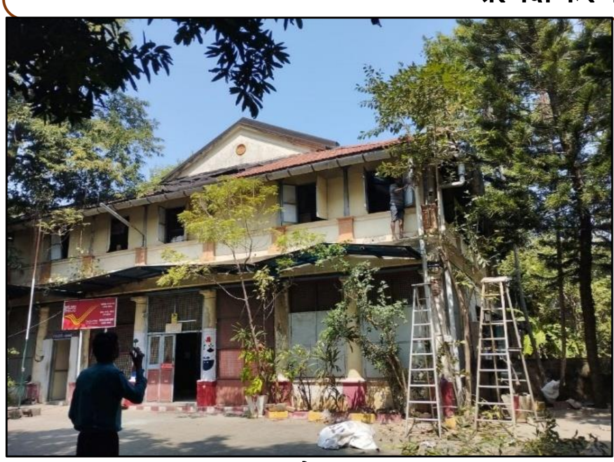

पहले

बाद में

डाक कार्यालय, पीएसडी,चेन्नई का नवीनीकरण, **डाक विभाग**

पहले

बाद में

एमसीएल, मुख्यालय, ओडिशा में स्वच्छता अभियान चलाया गया; **कोयला मंत्रालय**

5 पहले- बाद में

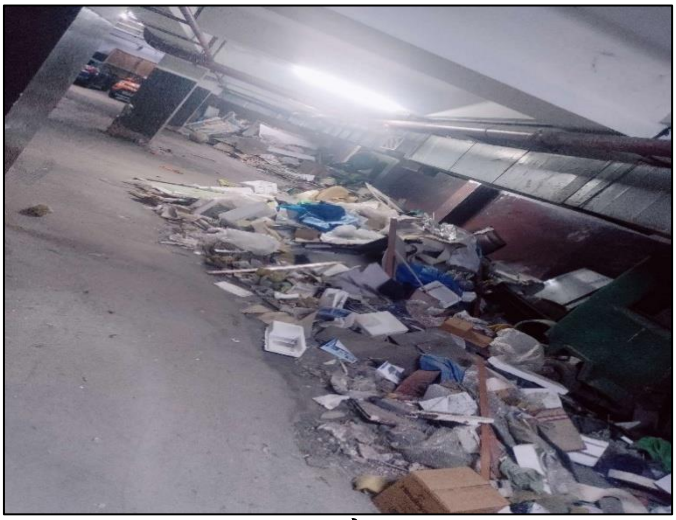

पहले

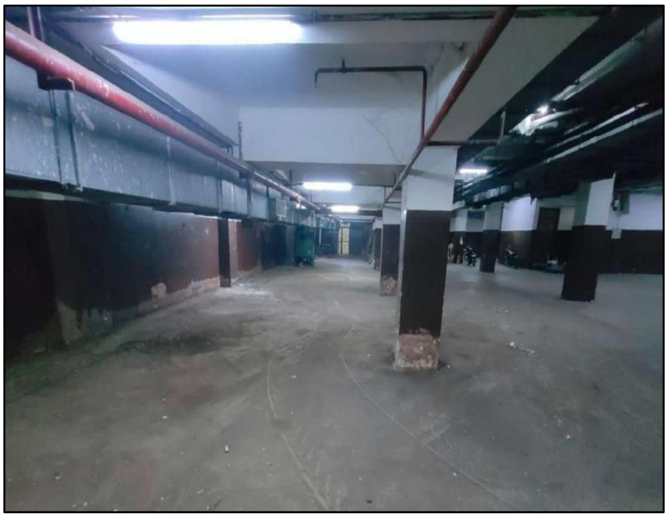

बाद में

पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया गया;

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

6 पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ

साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता में अग्रभाग का सौंदर्यीकरण; **परमाणु ऊर्जा विभाग**

रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद में लकड़ी की पैकिंग सामग्री से पौधों के गमले बनाए गए; **बायोटेक्नोलॉजी विभाग**

हानिकारक प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण की रक्षा के लिए कूड़े वाली जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया गया; **रक्षा विभाग**

बागवानी को बढ़ावा देते हुए बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद बनाया गया; टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई **परमाणु ऊर्जा विभाग**

7 मंत्रालयों/विभागों का मापदंड-वार कार्य-निष्पादन

मार्च, 2026 में निपटान के आधार पर शीर्ष 5 मंत्रालय/विभाग

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

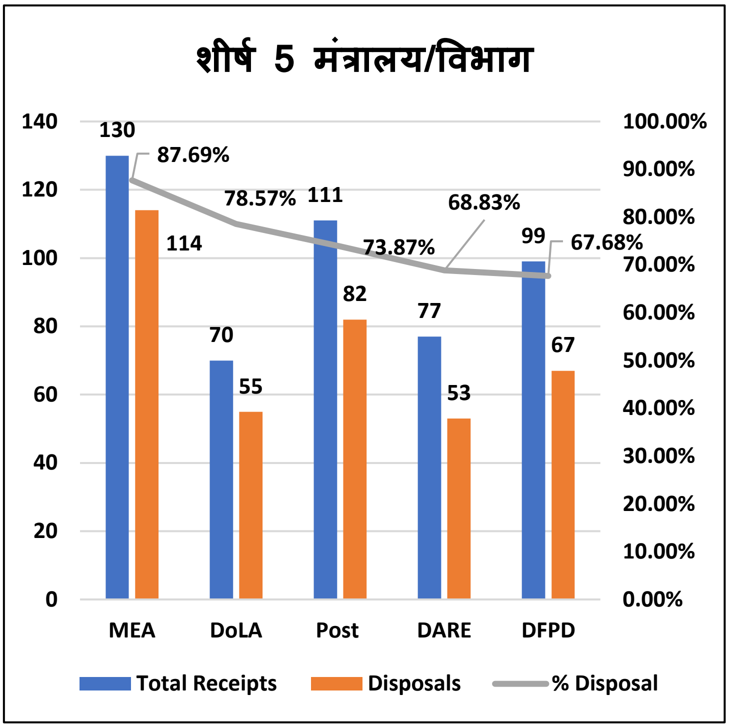

संसदीय आश्वासन

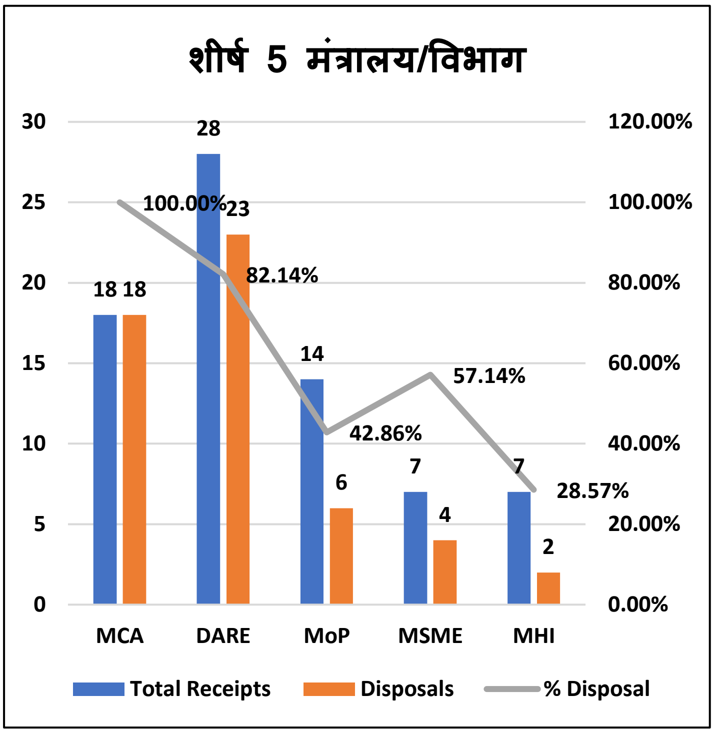

आईएमसी से प्राप्त पत्र

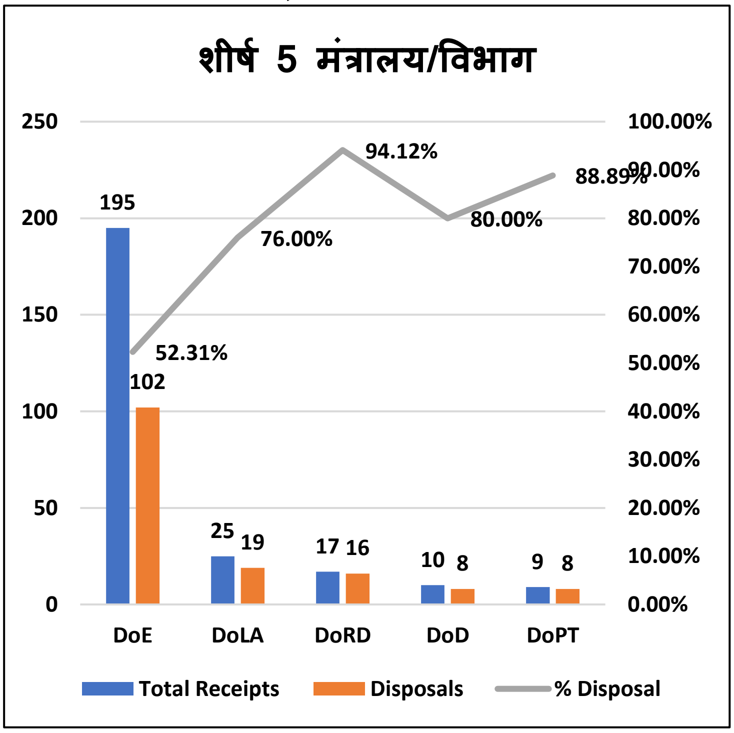

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र

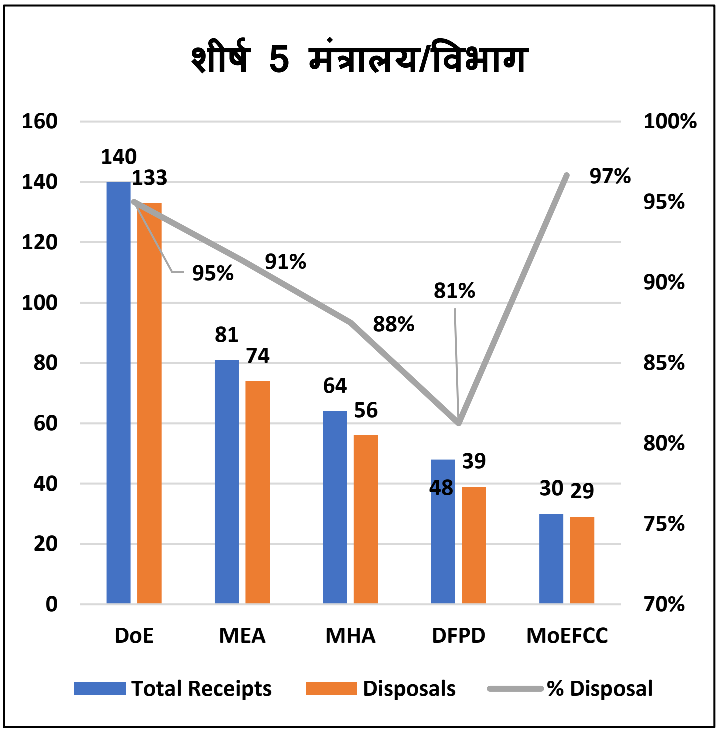

पीएमओ से प्राप्त पत्र

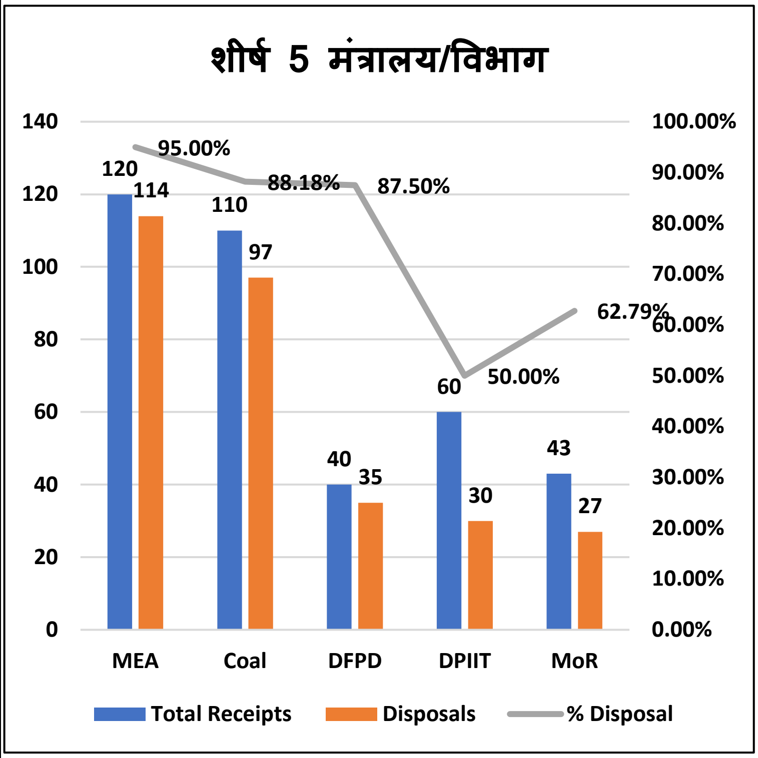

लोक शिकायत

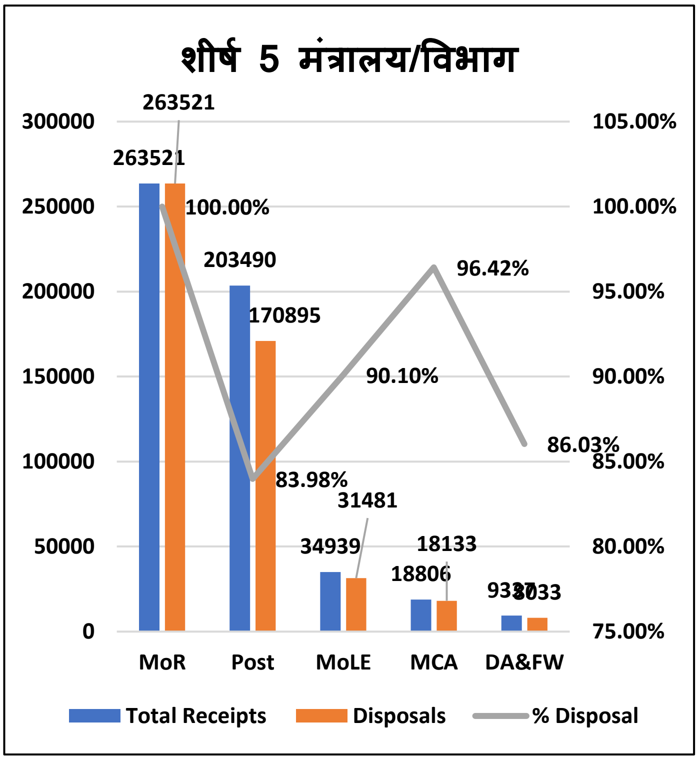

छंटाई की गई फाइलें

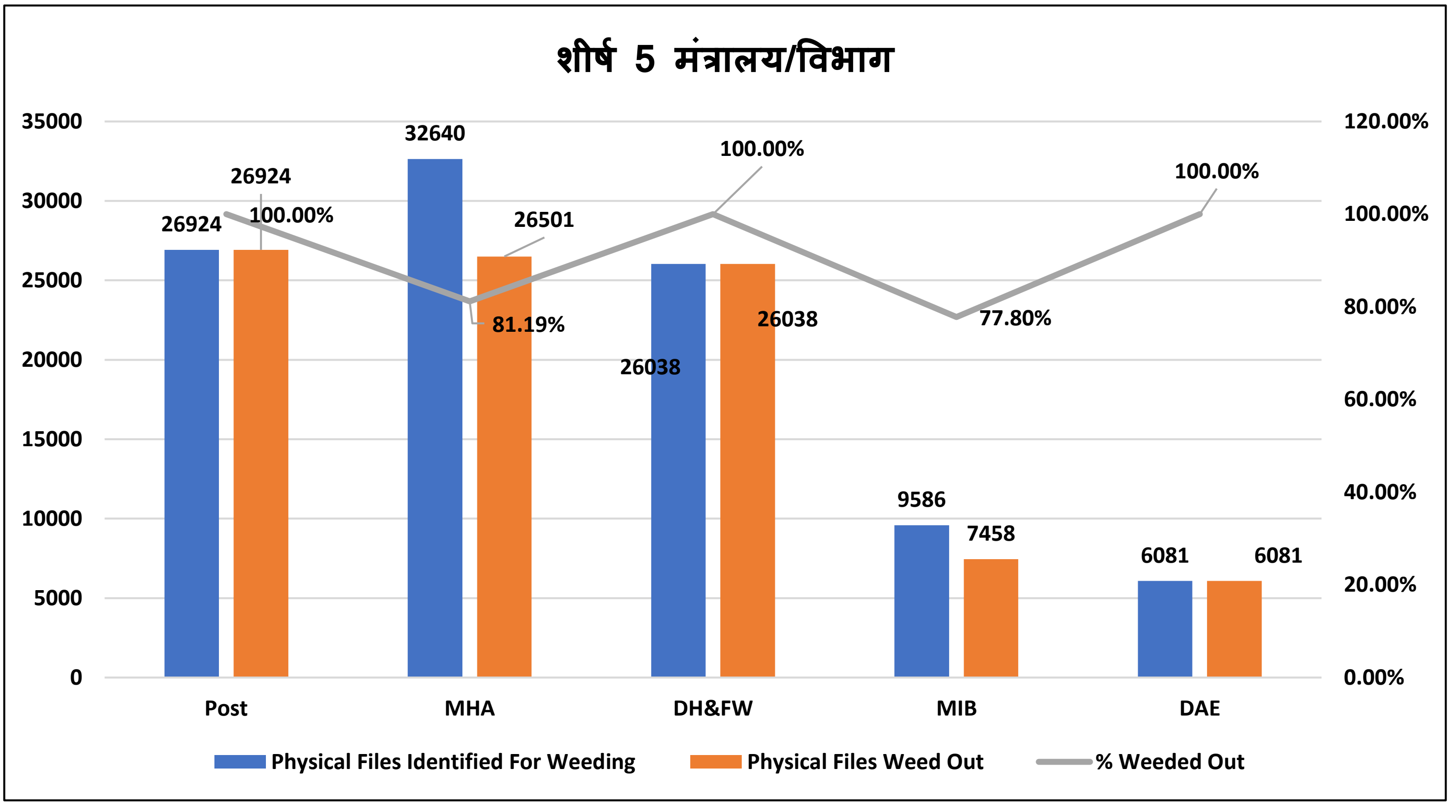

8 इन-फोकस: खान मंत्रालय

परिचय

डीएआरपीजी के मार्गदर्शन में, खान मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय संगठनों ने विशेष अभियान 4.0 (2024) और 5.0 (2025) में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें लंबित मामलों में कमी, शिकायत निवारण, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया। "गिविंग बैक टू नेचर" पर जोर देते हुए, मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन, सौर पैनल, जैव-खाद और वृक्षारोपण अभियान जैसी पहल की। विशेष अभियान 5.0 की थीम- "ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग" के तहत, जेएनएआरडीडीसी के माध्यम से समन्वित एक राष्ट्रव्यापी अभियान में 578 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिससे कचरा निपटान से 97 लाख रुपये की आय हुई, ~48,000 वर्ग फुट जगह खाली हुई और ~6,700 फाइलों की छंटाई की गई। मंत्रालय ने रिकॉर्ड प्रबंधन और संदर्भों के निपटान में 100 प्रतिशत लक्ष्य भी हासिल किए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 11 नियमों को सरल बनाया।

8.1. कार्यालय स्थान का कुशल प्रबंधन

मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय संगठनों के साथ रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, पुरानी वस्तुओं को हटाने और कार्यक्षेत्र के युक्तिकरण के माध्यम से कार्यालय स्थान की समीक्षा की। इसके परिणामस्वरूप, विशेष अभियान 4.0 और 5.0 में क्रमशः 1,65,119 और 48,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ। कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के लिए इन स्थानों को फिर से तैयार किया गया ।

8.2. कचरा निपटान

अप्रचलित फर्नीचर, ई-वेस्ट और अप्रयुक्त उपकरणों सहित स्क्रैप के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इन पहलों से न केवल स्थान खाली हुआ, बल्कि संसाधन दक्षता और सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों के अनुरूप , सरकार के लिए विशेष अभियान 4.0 और 5.0 के दौरान राजस्व के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ ।

8.3. सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ

वेस्ट टू वेल्थ पहलें

रानी लक्ष्मी बाई उद्यान पब्लिक पार्क में 1.6 टन एल्यूमीनियम स्क्रैप से तैयार की गई वेस्ट-टू-आर्ट की मूर्ति स्थापित की गई,एनएच-6, रायपुर

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा जबलपुर और हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों में मेटल स्क्रैप से कुर्सियां और कूड़ेदान बनाए गए

भारतीय खान ब्यूरो के नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी खदानों में विशेष अभियान 5.0 के तहत खदान स्थलों पर स्क्रैप से कला प्रतिष्ठान।

- **अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के सहयोग से ई-वेस्ट संग्रह अभियान चलाया गया**

(क) विशेष अभियान 5.0 के दौरान, जेएनएआरडीडीसी द्वारा समन्वित एक राष्ट्रव्यापी ई-कचरा पुनर्चक्रण अभियान, गोवा से शिलांग और दिल्ली से चेन्नई तक, व्यापक पहुंच और सरकारी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

• 11.72 टन वजन वाले कुल 4,775 ई-अपशिष्ट आइटम एकत्र किए गए और जिम्मेदारी से प्रमाणित पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप दिए गए।

• बरामद सामग्री से 19.34 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसे स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रूप से वितरित किया गया।

- **खनन स्थलों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान और स्वच्छता अभियान**

(क) चौपालों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव: स्वच्छता पहल में जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ावा देने वाला एक सहभागी मॉडल, जो अधिकारियों, श्रमिकों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद को सक्षम बनाता है

(क) **चौपालों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव:** स्वच्छता पहल में जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ावा देने वाला एक सहभागी मॉडल, जो अधिकारियों, श्रमिकों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद को सक्षम बनाता है।

केजीएफ में एनआईआरएम क्षेत्रीय कार्यालय भवन की चारदीवारी की सफेदी

पहले

बाद में

ग्रीन इनिशिएटिव्स

माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा **जीएसआईटीआई, हैदराबाद** में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

मध्य प्रदेश के मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट **में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया**

8.4. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना

डीएआरपीजी के निर्देशों के अनुसार, खान मंत्रालय ने समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए फाइल निपटान स्तरों और सबमिशन चैनलों की गहन समीक्षा की है। दिनांक 09.06.2021 के आदेश के माध्यम से डिलेयरिंग और प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, प्रस्तुतियों को अधिकतम चार स्तरों तक युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें ज्यादातर मामलों में अपर सचिव और संयुक्त सचिव सीधे सचिव (खान) को रिपोर्ट करते हैं। परिणामस्वरूप, फ़ाइल का औसत मूवमेंट स्तर काफी कम हो गया है।

- अनुदेशों के अनुपालन में, मंत्रालय ने डेस्क अधिकारियों के नौ (09) पदों का सृजन किया है, जिसने मंत्रालय के कार्य में दक्षता बढ़ाने में भी योगदान दिया है।
- मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2021 के आदेश के माध्यम से विभागाध्यक्षों (एचओडी) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में काफी वृद्धि की है, जिससे वित्तीय मामलों के निपटान में दक्षता में और वृद्धि हुई है।
- निर्णय लेने के स्तरों को संशोधित करने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त स्तरों पर अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए उपर्युक्त सभी आदेशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

8.5. उल्लेखनीय उपलब्धियां

विशेष अभियान 4.0 और 5.0 की अवधि के दौरान, खान मंत्रालय ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं:

- **100 प्रतिशत लोक शिकायतों और संदर्भों का निवारण किया गया।**

- **विशेष अभियान के दौरान 213945 वर्ग फुट क्षेत्र खाली किया गया।**

- **स्क्रैप निपटान के माध्यम से 20744808 रुपये का राजस्व अर्जित किया**

- **नियमों में आसानी।**

9. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
Dr. T.V. Somanathan

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

D.O. No. 502/2/2/2021-CA.V

27th November, 2024

Dear Secretary,

As you are aware, many initiatives have been undertaken in the recent years to make governance more responsive, accountable and transparent. The initiative for Increasing Efficiency in Decision Making, implemented since 2021, is a step in the same direction. It aims at achieving flatter and leaner organizational structures by putting in place appropriate delegation at various levels, rationalizing workload, thereby speeding up decision-making while increasing the productivity and efficiency of officers.

2. These measures have been incorporated into the Central Secretariat Manual of Office Procedure, 2022 wherein, it is emphasized that, each Ministry/Department will review the instructions on levels of disposal and channel of submission, keeping the number of levels to the minimum by delegating powers to lower formations. To facilitate quicker decision-making, the channels of submission should not be more than four.

3. However, it is observed that delayering is not being implemented in true spirit and a trend of increasing the channels of submission is observed in some Ministries/Departments. This is against the essence of the reforms undertaken so far and creates potential delays in file processing.

4. To sustain the measures undertaken as a part of Increasing Efficiency in Decision Making, you are advised to review the levels of disposal and channel of submission in your Ministry/Department and ensure that the levels do not exceed four and that the Special Secretary/ Additional Secretary/ Joint Secretary function independently as bureau heads.

5. I request you to devote your personal attention to this matter and ensure that these measures are implemented in letter and spirit, thereby fostering speedy and efficient decision making in Government.

With best wishes,

Yours sincerely,

(T.V. Somanathan)

To,

All Secretaries to Government of India

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004
Tel.: 011-23016696, 23011241 Fax : 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in

10. स्वच्छता और लंबित मामलों के त्वरित निपटान पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-11011/01/2025-O&M-DARPG (e-9571)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated: December 26, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Efforts aimed at Swachhata and expeditious disposal of pending matters in Government.

The Special Campaign 5.0 focussing on Swachhata and expeditious disposal of pending matters was conducted from October 2 – 31, 2025 by all Ministries /Departments. In order to institutionalise and sustain the momentum generated Ministries/Departments are requested to continue the following actions:

(i) System of Nodal Officers and Special Campaign Portal will continue. Nodal Officers to oversee institutionalisation/continuation of activities aimed at Swachhata and reducing pendency. Nodal Officers to also update the progress on the Portal,

(ii) Ministries/Departments may dedicate 3 hours every week for the activities as mentioned on the Portal **(www.scdpm.nic.in)**, and

(iii) Nodal Officers may review the progress of activities on a weekly basis and the Secretary of the Ministry/Department are requested to review the progress on a monthly basis.

This issues with the approval of competent authority.

(Sarita Chauhan)
Joint Secretary to Government of India

To
All Secretaries to the Government of India

Copy- All Nodal Officers of Special Campaign 5.0

11. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

MOST IMPORTANT

No O-16012/6/2017-ARC-DARPG (e2938)
Government of India
Ministry of Personnel Pensions and Public Grievances
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

6th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan
Janpath, New Delhi

Dated 17th January 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: eOffice Analytics - regarding.

*****

The undersigned is directed to say that the following guidelines may be adopted by Ministries / Departments for implementation of eOffice in Central Secretariat:

(i) Display their standing orders of delayering/Channels of Submission on their respective e-Office dashboard

(ii) Review Virtual Private Network (VPN) usage. Non-users may be identified and steps may be taken to deactivate / close the idle account after due examination and process. The NIC teams of Ministries/Departments may approach NIC VPN Division to obtain VPN data and for deactivation of idle VPN accounts

(iii) Follow the Manual of Office Procedure strictly and to avoid proliferation of part-files on the same subject. 'Common office function codes' as prescribed in Chapter - 6 'File Management System' of CSMOP 2022 are to be followed at the time of opening a new eFile in eOffice

(iv) Use of Knowledge Management System (KMS) for managing the OM's Circulars, Orders etc and further adding them as references in eFiles. Further, a list of all files (Division-wise/bureau-wise), in PDF, may be placed in the KMS for reference of all so as to avoid creation of multiple files in the same Head or part files

(v) Review the Designation Master in Personal Information Management System (PIMS) and identify the designations related to Personal Staff of officers. Based on the list of designations received from the Ministries / Departments, personal staff of Officers will be removed from the counts of distinct levels so that the actual distinct levels may be captured and reflected on the Analytics Dashboard

(vi) Review and examine the Distinct Levels. Ministries/Departments may refer to 'e-File Movement Status' Report under the 'Data Analytics' tab in the e-File MIS Reports application

Contd

11. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

-2-

(vii) Review the Basic File Head and notify the standardized Heads based on the relevant subjects of the Ministry/Department. Based on the list of Heads received from the Ministries/Departments, a consolidated list of Heads will be prepared which may be considered as standard Subjects to fetch the Subject-wise pendency.

(viii) The Ministries/Departments who process statutory clearance for various projects such as Ministry of Environment, Forest and Climate Change may provide expected time for clearance, so that the processing time of such files may be noticed.

(ix) E-Office Analytics to be developed to indicate file pendency at each level, to identify time delays and pendency. Emphasis to be given to identifying subject specific pendency across Ministries/Departments.

2. This issues with the approval of Secretary, DARPG.

सुनील सिंह

(Sunil K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.011-23440371
email: sunilk.singh73@nic.in

To

Secretaries to the Govt. of India

Copy to:

1. DG, NIC
2. Shri M.K. Mishra, DDG, NIC email: mk.mishra@nic.in
3. Shri Kapil Kumar Sharma, Sr. Director (IT), NIC
4. eOffice-PMU, NIC

Copy for information to:

PSO to Secy. (AR&PG)/PA to JS (SC) /DS (eOffice)

अनुलग्नक I: अपलोड नहीं किए गए आँकड़े

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
2	युवा कार्यक्रम विभाग
3	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
4	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
5	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
6	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
7	वस्त्र मंत्रालय
8	जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक II- संक्षेपाक्षरों की सूची

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
1.	सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर)
2.	सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3.	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
4.	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
6.	डीए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
7.	डीएएच	पशुपालन, डेयरी विभाग
8.	डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	डीबीटी	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
10.	डीसीपी	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
11.	डीओसी	वाणिज्य विभाग
12.	डीओसीए	उपभोक्ता मामले विभाग
13.	डीओडी	रक्षा विभाग
14.	डीओडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
15.	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
16.	एमओ डीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
17.	डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
18.	डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
19.	डीईएक्सडब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
20.	डीओई	व्यय विभाग
21.	डीओएफ	उर्वरक विभाग
22.	डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
23.	फिशरीज	मत्स्य पालन विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
24.	डीओएफपीडी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
25.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
26.	डीएचआर	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27.	डीएचई	उच्चतर शिक्षा विभाग
28.	दीपम	विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
29.	डीओजे	न्याय विभाग
30.	डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
31.	डीओएलए	विधि कार्य विभाग
32.	डीएमए	सैन्य कार्य विभाग
33.	डीओएल	राजभाषा विभाग
34.	डीपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
35.	डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
36.	डीओपीएच	औषध विभाग
37.	पोस्ट्स	डाक विभाग
38.	डीओपीई	लोक उद्यम विभाग
39.	डीओआर	राजस्व विभाग
40.	डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
41.	डीओएसईएल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
42.	डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
43.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
44.	डीओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
46.	स्पोर्ट्स	खेल विभाग
47.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
48.	डीओडब्ल्यू आर एंड आरडी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
49.	डीओवाईए	युवा कार्यक्रम विभाग
50.	एलडी	विधायी विभाग
51.	आयुष	आयुष मंत्रालय
52.	एमओसीए	नागर विमानन मंत्रालय
53.	कोल	कोयला मंत्रालय
54.	को-ऑपरेशन	सहकारिता मंत्रालय
55.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
56.	एमओसी	संस्कृति मंत्रालय
57.	डीओडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
58.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
59.	एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
60.	माइटी	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
61.	एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
62.	एमईए	विदेश मंत्रालय
63.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
64.	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
65.	एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
66.	एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
67.	एमएचए	गृह मंत्रालय
68.	एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
69.	एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
70.	एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
71.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
72.	एमओएम	खान मंत्रालय
73.	एमओएएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
74.	एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभागका नाम
75.	एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
76.	एमपीए	संसदीय कार्य मंत्रालय
77.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
78.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
79.	एमओआर	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
80.	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
81.	एमओपीएसडब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
82.	एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
83.	एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
84.	एमओएस	इस्पात मंत्रालय
85.	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय
86.	टूरिज़्म	पर्यटन मंत्रालय
87.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
88.	एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
89.	एमओवाईएस	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
90.	नीति आयोग	नीति आयोग

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग , नई दिल्ली - 110001